नीति निर्माण में निर्भीकता से दी गई सही सलाह महत्वपूर्ण

दिवंगत कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी की श्रद्धांजलि सभा में बोलते हुए भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मुरलीमनोहर जोशी ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निर्भीक और सही सलाह देने वालों की बेहद जरूरत है'। जोशी की बात को ख़ारिज करना गलत होगा। आंकड़े लगातार बताते हैं कि आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। योजनाओं के उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बनाने के पहले और अमल के लिए विशेषज्ञों की स्वतंत्र राय लेने की प्रक्रिया एकल नेतृत्व (जैसे मोदी की है) में नदारद रहती है। लेबर ब्यूरो के एक सर्वे (अप्रकाशित) के अनुसार मुद्रा योजना में केवल पांच लाभार्थियों में एक ने ही कोई नया काम शुरू किया और एक रोजगार के लिए सरकार का पांच लाख से ज्यादा रुपया खर्च हुआ, जबकि शेष लोन पहले से व्यवसाय कर रहे लोगों ने लिया। यानी योजना का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो सका। किसान की आय 2022 तक दूनी करने का एलान हकीकत से इतर तस्वीर पेश करता है। किसान उत्पादन तो बढ़ा रहा है, लेकिन उत्पादकता कम होती जा रही है। कारण उपज की मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था न होना, जिससे कीमतें कम रही। उधर, रासायनिक खादों के दाम बढ़ने से लागदत ज्यादा रही। ऐसे में जीरो बजट खेती का नया राग दशकों से जारी खेती के तरीके को बदलने का जोखिम है। बगैर यह सुनिश्चित किए कि रात में हुई घोषणा के बाद कैश के गायब होने से धनिया बेचने वाली बुढ़िया को साहूकार उधारी पर अनाज भी नहीं देगा या एटीम में ट्रे का साइज़ और नए नोट का साइज़ बदल जाने के कारण मजदूर पैसे के बिना दवा कहां से कराएगा। नोटबंदी के लिए मोदी सरकार को जन-निंदा झेलनी पड़ी। इससे बचा जा सकता था अगर निर्भीक सलाह देने वाले योजना लागू करने के साथ विकल्प भी सुझाते, लेकिन आज आम धारणा यही है कि देश में केवल दो ही लोग शासन चला रहे हैं- प्रधानमंत्री और गृहमंत्री। प्लास्टिक रहित भारत अच्छा नारा है, लेकिन कपड़े का थैला तब तक विकल्प नहीं बन पाएगा जब तक बड़े पैमाने पर और प्लास्टिक जैसा ही सस्ता कपड़े का झोला नहीं मिलता। निर्भीक और सही सलाह तथा समुचित तैयारी के बाद यह अपील लोगों को भविष्य में भी अपने नेता की बात पर उत्साह से अमल के लिए प्रोत्साहित करेगी। अरुण जेटली के निधन के बाद यह और भी जरूरी है।

सुशासन से भारत में घुलेंगे-मिलेंगे कश्मीरी

संदर्भ... हमारा सामना इस असुविधाजनक सत्य से है कि हिंदुत्व व कश्मीरियत सहित हर राष्ट्रवाद काल्पनिक है

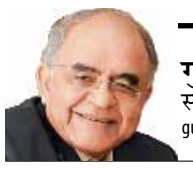

गुरचरण दास
स्तंभकार व लेखक
gurcharandas@gmail.com

कश्मीर के राजनीतिक दर्जे में किए बदलाव से कश्मीरियों में गुस्सा, भय, अलगाव और आत्म-सम्मान खोने की भावना है। कई लोगों ने कश्मीरियत को पहुंची चोट को कानूनी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है लेकिन, जरूरत राष्ट्रीय पहचान की दार्शनिक समझ की है। खासतौर पर कश्मीरियों और भारतीयों को इस तथ्य को समझना होगा कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पहचानें काल्पनिक हैं। हिंदुत्व और कश्मीरियत दोनों आविष्कृत अवधारणाएं हैं। इससे कुछ रोष शांत करने में मदद मिलेगी।

कश्मीर में आलोचना हो रही है कि कश्मीरियों की सहमति ऐसे तो नहीं ली जानी चाहिए थी। हालांकि, लंबी अवधि में यह रोष चला जाएगा यदि कश्मीरियों को भारत साथ रहने लायक लगा। भारत कई पहचानों का संघ है और कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या कश्मीरी पहचान को पहुंची चोट, आंध्र के लोगों के गर्व को पहुंची चोट के दुख से भिन्न है, जो कुछ ही साल पहले अपने राज्य का आधा हिस्सा खो बैठे हैं? कुछ अन्य लोगों ने दलील दी है कि कश्मीर सीमावर्ती प्रदेश है, जिसका कुछ इतिहास है, जो इसे अनूठा बनाता है। लेकिन, फिर पंजाब जैसे अन्य सीमावर्ती प्रदेश हैं, जहां के लोगों ने अपने घर व परिजनों को बंटवारे के वक्त खोया। बाद में पंजाब का हरियाणा व हिमाचल में और विभाजन हुआ। क्या पंजाब या आंध्र के लोगों से इनके बारे में पूछा गया था?

कुछ उदारवादी मानते हैं कि जनमत संग्रह ही सहमति प्राप्त करने का एकमात्र असली तरीका है और कश्मीरियों को आत्म-निर्णय के सिद्धांत के आधार पर अलग होने का विकल्प दिया जाना चाहिए। यदि यह सही है तो क्या हम आंध्र में भी जनमत संग्रह कराने के लिए नैतिक रूप से बंधे नहीं हैं? यदि इस सोच को पीछे 1947 में ले जाए तो क्या हमें यह सिद्धांत 565 रियासतों के नागरिकों पर लागू नहीं करना था, जो अंग्रेजों की विदाई के वक्त भारत के 40 फीसदी भू-भाग पर रहते थे। कश्मीर तो इनमें से केवल एक था। डॉ. आम्बेडकर को लगता था कि भारत 3000 जातियों का राष्ट्र है तो क्या 3000 जनमत-संग्रह कराए जाने चाहिए थे? क्या ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीयों को भी विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए था कि वे भारतीयों से शासित होना चाहते हैं या अंग्रेजों से? यदि पर्याप्त संख्या में भारतीय चाहते कि ब्रिटिश शासक बने रहे तो शायद कभी भारत नाम का स्वतंत्र देश ही नहीं होता। जनमत संग्रह असमंजस की स्थिति भी बना सकता है, जैसा कि ब्रेक्ज़िट के बाद ब्रिटेन को अहसास हो रहा है। समान वंश परम्परा, भाषा और साझा संस्कृति के आधार पर नेशन-स्टेट (राष्ट्र-सत्ता) के निर्माण का विचार हाल का आविष्कार है। यह विचार मध्य यूरोप में चले 30 साल के विनाशकारी संघर्षों को खत्म करने वाली वेस्टफालिया (1648) की संधि में जन्मा था। 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद भी यूरोप ज्यादातर साम्राज्यों व रियासतों में बंटा था। उसके बाद यूरोप के लोग सोच-विचार कर राष्ट्र-सत्ता के गठन में लगे। चूंकि प्राकृतिक एकता तो आमतौर मौजूद नहीं थी तो उनके नेताओं ने इसका 'निर्माण' किया और स्कूली पाठ्यक्रमों में इतिहास के पौराणिक संस्करणों के जरिये लोगों के गले उतार दिया। आज हिन्दू राष्ट्रवादी भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रिय राष्ट्रवाद के कारण हुए निरर्थक प्रथम विश्वयुद्ध के खौंफ का यह नतीजा रहा कि दुनिया 1920 के दशक में आत्म-निर्णय के नैतिक विचार की आकर्षित हुई। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को भी अहसास हुआ कि स्व-शासन का उनका दावा यह सिद्ध करने पर निर्भर है कि उनका देश एक राष्ट्र है। इस तरह महात्मा गांधी हमारे मुख्य 'मिथमैकर' या आख्यान-निर्माता बन गए।

आज भारत में कश्मीर के एकीकरण से इसी प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं : राष्ट्र-सत्ता क्या है? इस विचार के आविष्कारक कहेंगे कि यह एक भावना है, 'फेलो फिलिंग', साथ रहने से उपजी सह-भावना, जो भारतीयों को एकजुट करती है। समस्या यह है कि यह उनके प्रति विद्वेष में बदलती है, जो भिन्न हैं। हो सकता है कि कश्मीरी मुस्लिम विरोध करें कि उनमें हिन्दुओं के लिए 'फेलो फिलिंग' नहीं है और पाकिस्तान के निर्माण के पीछे भी यही दलील थी। ज्यादातर राष्ट्रों में कई धर्म हैं, यहां तक कि मुस्लिम भी कई देशों में अल्पसंख्यकों के रूप में रहते हैं। इस तरह धर्म राष्ट्रीयता के लिए ठोस आधार नहीं है।

'फेलो फिलिंग' का एक और स्रोत जश्न और तकलीफों की साझा यादें भी हो सकती हैं। ऐतिहासिक स्मृतियों के साथ समस्या यह है कि वे बांट भी सकती हैं। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला मोहम्मद गजनी हिन्दुओं की दृष्टि में खलनायक है और मुस्लिमों के लिए नायक। इसलिए यह मानक भी नाकाम है। राष्ट्र निर्माण के लिए इतिहास को भूल जाना प्रायः बेहतर होता है। चूंकि राष्ट्र-सत्ता की पहचान के सारे मानक नाकाम हो गए हैं तो हमें इस असुविधाजनक सत्य का सामना करना पड़ेगा कि राष्ट्र एक 'काल्पनिक समुदाय' है, जैसा कि आयरिश राजनीतिक विज्ञानी बेनेडिक्ट एंडरसन ने हमें सिखाया है। पहचान का इससे कोई संबंध नहीं है। सारे आधुनिक राष्ट्र-राज्य और क्षेत्रीय पहचानें कृत्रिम निर्मितियां हैं, जिसमें ज्यादातर नागरिक अजनबी हैं, जो कभी नहीं मिल पाएंगे। कोई जोड़ने वाला प्राकृतिक तत्व नहीं है जो भारत या किसी अन्य देश अथवा कश्मीर, बंगाल या आंध्र जैसे राज्यों को जोड़े। हिन्दू राष्ट्रवादियों और कश्मीरी पृथकतावादियों को यह समझने की जरूरत है। हिंदुत्व और कश्मीरियत दोनों काल्पनिक है। भारत का आविष्कार 26 जनवरी 1950 को इस आधार पर हुआ कि जो भी इसके भौगोलिक क्षेत्र में रहता है उसे अधिकतम समान स्वतंत्रता मिलेगी और कोई दोयम दर्जे का नागरिक नहीं होगा।

कश्मीरियों का सफल व रोष रहित समावेश अंततः इस बात पर निर्भर होगा कि सामान्य कश्मीरी की निगाह में भारत कितना वांछनीय लगता है यानी वह कितना पसंद आता है। इस मामले में भारतीय राष्ट्र-राज्य का काम महत्वपूर्ण है। वह सुशासन से सुनिश्चतता कायम करें, यह पक्का करे कि हर कोई कानून के सामने समान है, लोगों को अपने शासक बदलने का विकल्प उपलब्ध कराए, शिक्षा व सेहत की बेहतरी के अवसर प्रदान करें और समृद्धि की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां निर्मित करे। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

खुद को भुलाकर ये काम कभी न करें

जीने की राह
पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें छुपाने में बड़े माहिर होते हैं। ऐसा कहते हैं कि उनकी पाचनशक्ति बहुत मजबूत होती है। पता ही नहीं चलता उनके भीतर क्या चल रहा है और बाहर से क्या दिख रहा होता है। लेकिन फकीरों ने कहा है- कुछ नशे ऐसे होते हैं जो छुपाए नहीं छुपते। यदि इन सात कामों का नशा चढ़ गया तब तो दुनिया इसको जान ही लेगी। इसलिए कहा है- खैर, खून, खांसी, खुसी, बैर, प्रीति, मदपान। रहिमन दाबे न दबै, जानत सकल जहान।। खैरियत यानी सबकुछ ठीक-ठाक का हल्ला, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और मदिरा.., यदि आपने इनका नशा किया है तो इसकी प्रतिक्रिया आपके आचरण में आएगी ही और आप छुपा नहीं पाएंगे। शराब के नशे के उपद्रव तो अपराध के रूप में हम देख ही रहे हैं। तो कोशिश यह करें कि इनको नशा न बनाएं। वैसे तो नशा हर चीज का बुरा है, पर इन सात चीजों का तो छिपेगा भी नहीं। नशा मतलब अनुभूति की अधिकता। बिना सोचे-समझे किसी बात को अपने भीतर उतार लेने को भी नशा कहते हैं। नशा किए बिना इन्सान मानेगा भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये सात काम जिंदगी में हो सकते हैं। इनमें से कुछ तो होना भी चाहिए, लेकिन उसे नशा मत बना लेना। मनुष्य नशा करता ही इसलिए है कि स्वयं को भूल सके और इन सातों कामों में स्वयं को याद रखना है। यदि खुद को भुलाकर इनमें से कोई काम किया तो मानकर चलिए आप अपने अच्छे काम को भी अपराध में बदल रहे होंगे..।

जीने की राह कॉलम पं. विजयशंकर मेहता जी की आवाज में मोबाइल पर सुनने के लिए 9190000072 पर मिस्ड कॉल करें

अरज करे धरती की दाई, रात कभी भी बांझ न हो!

सुर्खियों से आगे
▪ नवनीत गुर्जर
नल एडिटर, डीबी डिजिटल

देश में लोग हैं। सरकार भी है। लोग इसलिए होते हैं कि वे वोट देकर एक सरकार चुन सकें। सरकार इसलिए होती है कि जिन लोगों ने उसे बनाया, वह उन्हें चला सके। सरकारें बनती जाती हैं। लोग चलते जाते हैं। इन दिनों देश में दो ही बातें चल रही हैं। पहली 370 और दूसरी आर्थिक मंदी। 370 का कमाल ये है कि झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और किसी को लोकल मुद्दों की पड़ी नहीं है। न लोगों को। न सरकारों को। इन तीनों राज्यों में छोटे दल ज्यादा हैं। लेकिन उनकी कोई चर्चा तक नहीं करता। जैसे 370 ने छोटे दलों के मुंह पर हल्दी पोत दी हो! सबकुछ एकतरफ़ा लग रहा है। जहां तक मंदी की बात है, खबरें छन- छन कर आ रही हैं। चर्चा भी ख़ूब है, लेकिन उपाय के नाम पर कुछ नहीं। न लोगों की तरफ़ से। न सरकार की ओर से।

मंदी 2008 में भी आई थी लेकिन इस बार दिवाली के पहले ही चौखट पर आ बैठी लगती है। नौकरी, व्यापार, बाज़ार, सबकुछ लुटता नज़र आता है। ऐसे में सिर पर दिवाली! कहते हैं सालभर का घाटा भी दिवाली पर पूरा हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता। हां, चुनावी ख़र्च पर इसका कोई असर नहीं दिखने वाला। क्योंकि यह संकट धरती का है और चुनाव में होने वाला ख़र्च आसमान से टपकता है। इस ख़र्च से बाज़ार पर भी कोई असर नहीं होने वाला। क्योंकि इसे दबे पांव ख़र्च किया जाता है। कोई देख न ले। कोई सुन न ले। देश मंदी के गर्त की तरफ़ बढ़ रहा है और राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जीतने की पड़ी है। याद आती है गुलज़ार की एक नज़्म...

कितने मासूमों के घर
दंगों में मलबे का ढेर हो जाते हैं
और ये चिड़िया है!
एक टूटे हुए रोजन में इसे
तिनके सजाने की पड़ी है!!

खैर मंदी कम से कम भारत का तो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। 2008 में भी दुनियाभर में मंदी आई थी, लेकिन हम पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। तब और अब में फर्क सिर्फ इतना है कि तब हमारी छोटी बचत के छोटे छोटे पारम्परिक जरिए जिंदा थे, जबकि अब नोटबंदी उन बचतों के प्राण पी चुकी है। फिर भी हममें मंदी से लड़ने की ताकत है और आख़िर, इससे भी पार पा ही लेंगे। हमारे घरों में बचत की जो मानसिकता है, कम से कम ख़र्च करने या खर्च के मामले मे फूंक-फूंक कर क़दम रखने की जो आदत है, उसे कोई नोटबंदी हमसे छीन नहीं सकती। बस, यही एक आशा की किरण है, जिस पर हम टिके रहेंगे और जीतेंगे भी।

कहते हैं एक आशा!
किरणों की कोख में आई है,
पूरब ने एक पालना बिछाया!
सुना है नया सूरज,
रात की कोख में है!
अरज करे धरती की दाई,
रात कभी भी बांझ न हो!
पीड़ा कभी भी बांझ न हो!!

वेब भास्कर

फोटोग्राफी... दुनिया का सातवां सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट फूजी, 100 किमी दूर टोक्यो से भी आता है नजर

यह फोटो जापान के होंगशू प्रांत में स्थित माउंट फूजी का है। यह एशिया का दूसरा और दुनिया का सातवां सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 12,389 फीट है। यह पर्वत टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर होने के बावजूद मौसम साफ रहने पर नजर आता है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और साल के पांच महीनों में बर्फ से ढंका रहता है। • travelphotodiscovery.com

इंटरेस्टिंग... तूफान से बचाने 97 डॉगी को दी घर में पनाह

नासाऊ (कैरेबियन द्वीप समूह का देश बाहमास) । यहां लगातार कई दिनों से आ रहे समुद्री तूफान ने पूरे द्वीप का जन-जीवन तहस-नहस कर रखा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है तो कई मवेशी बह गए हैं। हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित करने में लगा हुआ है तो किसी को परिवार तथा घर की सुरक्षा की चिंता है। ऐसे माहौल में चेला फिलिप्स नामक महिला के दयालु स्वभाव की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने द्वीप के 97 डॉगी की जान बचाने के लिए उन्हें अपने घर में पनाह दे रखी है।

वॉशिंगटन पोस्ट में चेला फिलिप के काम की खूब सराहना की गई है। चेला के अनुसार मंगलवार 3 सितंबर तक उन्होंने एक-एक कर 97 डॉगी रेस्क्यू कर अपने घर में रखे। यहां तक कि उनके बैडरूम में भी कुछ डॉगी पनाह लिए हुए हैं। चेला इन्हें नाश्ता व भोजन भी दे रही हैं। यदि वे इन डॉगी की सुरक्षा नहीं करतीं तो इनमें से

कई तूफान की भेंट चढ़ चुके होते, क्योंकि पूरे द्वीप पर बाढ़ आई हुई है। सैकड़ों घर नष्ट हो चुके हैं, कारें बह गई हैं और हवाई अड्डे पूरी तरह बंद हैं। मनुष्य अपनी जान बचा नहीं पा रहे हैं, ऐसे में इन जानवरों की सुरक्षा करने की किसे परवाह होगी?

उन्होंने इस काम के फोटो फेसबुक सहित अन्य साइट पर पोस्ट की है। इसके बाद लगातार लोग उन्हें मदद करने के लिए मैसेज भेज रहे हैं। उनकी फेसबुक पोस्ट के अनुसार 79 डॉगी उन्होंने अपने विशाल मास्टर बैडरूम में रखे हुए हैं। मेरे लिए एक अच्छी बात यह है कि डॉगी मेरे बिस्तर पर नहीं कूद रहे हैं, न ही उसे गंदा कर रहे हैं। ये आपस में दोस्त बन चुके हैं। उन्होंने अपने पशु शरणार्थी शिविर की मदद के लिए फेसबुक पर क्राउड फंडिंग के लिए पोस्ट डाली तो देखते ही देखते उसमें 73 हजार डॉलर जमा हो गए। यह राशि उनके अनुमान से तीन गुना अधिक है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, फिलिप्स पिछले 15 वर्षों में एक हजार से अधिक बेघर डॉगी की मदद कर चुकी हैं। संयुक्त राज्य में उन्होंने 200 डॉगी के लिए एक घर बनाकर दिया है। उन्होंने अपने पेज पर लिखा है कि कोई काम असंभव नहीं होता, हमें इन प्राणियों के लिए कुछ करना है तो समय निकालना पड़ता है। ये सभी प्यार के भूखे हैं, भोजन से ज्यादा इन्हें दुलार चाहिए। आप बस हमारे लिए प्रार्थना करें। • washingtonpost.com

18 लाख करोड़ पा चुके उद्योग जगत को नहीं, किसान को सीधी मदद देने से होगा उद्धार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने से आई है आर्थिक मंदी

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने असाधारण कदम उठाने का आह्वान करते हुए मौजूदा मंदी को शायद 70 वर्षों में सबसे खराब बताया है। यह जानने के बाद भी नीति आयोग ने खतरे की घंटी नहीं बजाई कि 2000 से 2017 के बीच 17 वर्षों में भारतीय किसानों ने 45 लाख करोड़ रुपए का कमरतोड़ नुकसान झेला है। सत्तर साल के सबसे खराब दौर से गुजरते कृषि क्षेत्र की दशा पर मुख्य धारा के अर्थशास्त्री और नीति निर्माताओं ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ओईसीडी-आईसीआरआईईआर के अध्ययन के मुताबिक किसान अपनी जायज आय से वंचित हुए, जिससे उन्हें 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। नेशनल सैम्पल सर्वे के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 की लीक हुई रिपोर्ट ने बताया कि 2011-12 से 2017-18 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में 3.4 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए, इनमें से 3 करोड़ तो खेतिहर हैं। भीषण ग्रामीण आर्थिक संकट के चिह्न स्पष्ट हैं।

खुली बात
▪ देविंदर शर्मा
कृषि विशेषज्ञ

संकट को तभी महसूस किया जाता है,जब उद्योग जगत खराब प्रदर्शन करता है। यदि नीति आयोग खेती के गंभीर संकट के प्रति जाग जाता तो मंदी की आंच इतनी नहीं होती। यह मुख्यतः घरेलू मांग में होती गिरावट का नतीजा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने से आई है। नकदी की उपलब्धता में गिरावट का इससे कोई संबंध नहीं है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि आय में 'शून्य के करीब' वृद्धि और आधे प्रतिशत से भी कम की कृषि सेक्टर वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत स्पष्ट है। सार्वजनिक क्षेत्र के घटे निवेश से स्थिति और गंभीर हो गई है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने ही बताया है कि यह 2011-12 और 2016-17 के बीच जीडीपी के 0.3 से 0.4 फीसदी के बराबर रहा है। जहां संकट खेती में है वहीं उद्योग जगत ने रो-धोकर शोर मचाया कि कैसे आटो सेल्स गिर रहा है और रियल एस्टेट उद्योग में सामान बिना उपयोग के इकट्ठा हो रहा है। ऐसा दबाब डालकर 1 लाख करोड़ रुपए की रियायत मांग रहे उद्योग जगत को मीडिया के एक बड़े तबके का भी समर्थन मिल रहा है। किसान और ग्रामीण गरीब फिर एक बार भुला दिए गए।

हर कोई सहमत है कि मंदी मुख्यतः ग्रामीण मांग ध्वस्त होने का नतीजा है। क्या यह स्थिति वैसी ही नहीं है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रह्मण्यम ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत की 'मुनाफे का निजीकरण और घाटे का सामाजीकरण करने की प्रवृत्ति' कहकर वर्णित किया था? क्योंकि 2007 से पिछले 12 वर्षों में 8.5 लाख करोड़ का फंसा हुआ लोन माफ कर दिया गया और बैंकों के सामने 17 लाख करोड़ का ऐसा ही और लोन मुंह बाएं खड़ा है। इसमें से 12 लाख करोड़ के आने की संभावना नहीं है। 2009 से वैश्विक आर्थिक मंदी के दिनों से उद्योग जगत को हर साल 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज मिल रहा है। यानी उसे 10 वर्षों में 18 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। उसे जीडीपी के 5 फीसदी के करीब टैक्स रियायतें भी मिली हैं। जब सरकार घाटे में फंसी एयर इंडिया को प्रोत्साहन पैकेज देती है तो इंडस्ट्री उसका निजीकरण करने को कहती है तो, क्या घाटे में जा रहे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए?

जब सबकी निगाह 1.76 लाख करोड़ रुपए की उस लाइफ लाइन पर है, जो रिजर्व बैंक ने मुहैया कराई है, तो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का सबसे अच्छा तरीका ग्रामीण गरीबों के हाथों में अधिक पैसा उपलब्ध कराना ही है। यह देखते हुए कि 17 राज्यों यानी मोटे तौर पर देश के आधे हिस्से में कृषक परिवार की औसत आय 20 हजार रुपए ही है, कैश रिजर्व का उपयोग प्रधानमंत्री किसान योजना के मार्फत किसानों को सीधे सहायता देकर उनकी आय दोगुनी करने में किया जाना चाहिए। फिलहाल जमीन वाले किसानों को 6 हजार रुपए सालाना मदद दी जा रही है, इसे दोगुना कर देना चाहिए। भूमिहीन किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान योजना के दायरे में लेने का यही वक्त है। शुरुआत वादे के मुताबिक 20 हजार गांवों के हाटों को आधुनिक मंडियों में तब्दील करने के प्रयासों में तेजी लाने से करनी चाहिए।

नॉलेज भास्कर | ऐसे बनाएं शिक्षण में कॅरियर-III

पहले से डाउनलोड किया एडमिट कार्ड साथ रखें

ऑनलाइन फीस जमा करने के कई विकल्प हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करना चाहे तो 'कार्ड भुगतान' ऑप्शन पर या नेट बैंकिंग करना चाहें तो 'नेट बैंकिंग' पर क्लिक करें। ई-चालान से नकद जमा करना चाहें तो कर सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों की फीस जमा हो चुकी है और उनके सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं तो ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी एनटीए की वेबसाइट पर उनके रोल नंबर, दिनांक और शिफ्ट (परीक्षा की समय सीमा) के साथ डाल दी जाती है। यदि उम्मीदवार ने फीस जमा कर दी है और उसके नाम का विवरण एनटीए की वेबसाइट पर अंतिम सूची में भी नहीं दिखाया गया है तो ऐसे लोगों को अपने कुछ दस्तावेजों के साथ हेल्प लाइन (नंबर-7042399520) पर संपर्क करना चाहिए। इन दस्तावेजों में फीस जमा करने की रसीद, यदि ऑनलान जमा की है तो उसका प्रिंट आउट एनटीए की वेबसाइट पर डालें। इसके बाद अपने मोबाइल पर एसएमएस चेक करते रहें, साथ ही ई-मेल लगातार देखते रहें। जिन आवेदकों का सब कुछ सही चल रहा है, वे एनटीए की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो हेल्प लाइन 7042399520 पर संपर्क करना चाहिए। परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड के निर्देशों को ध्यान से पढ़कर उनका पालन करें। यदि फोटो, साइन या प्रवेश-पत्र में कोई त्रुटि है तो तुरंत हेल्प लाइन पर संपर्क करें। ऐसे मामलों में पहले से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा दे सकते हैं।

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी)

कम्प्यूटर आधारित टेस्ट के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं, वे आप यूजीसी की वेबसाइट www.ntanet.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। यह टेस्ट देने के लिए उम्मीदवार को उन्हें बताए गए कंप्यूटर के सामने बैठाया जाता है। लॉग इन करने के बाद उम्मीदवार को निर्देश मिलते रहते हैं, उसी के अनुसार निर्धारित समय पर वे माउस का उपयोग कर प्रश्नों को हर कर आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीदवारों के पास किसी भी समय पहले से दर्ज, संपादित उत्तर देने का विकल्प होगा।

परीक्षा हॉल में अनिवार्य रूप से लाएं

अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर केंद्र पर पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। **1.** NTA की वेबसाइट से डाउनलोड एडमिट कार्ड का प्रिंट। **2.** परीक्षा केंद्र के उपस्थिति पत्रक में चिपकाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो। **3.** कोई एक फोटो आईडी (पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या आधार कार्ड)।

ध्यान देने योग्य जरूरी बातें

- उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्रों पर UGC-NET के लिए डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा।
- एडमिट कार्ड को म्यूट नहीं करें और न ही उसमें दर्ज जानकारी को बदलें।
- अपने एडमिट कार्ड को रिकॉर्ड के रूप में अच्छी स्थिति में रखें।
- विकलांग उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विकलांगता का प्रकार और प्रतिशत सही ढंग से भरे।